1	2	3	4	5
चंडीगढ़	1	7996	4468	30/6/96
दादरा व नगर हवेली	1	20	10	30/6/96
दमण व दीव	2	32	16	30/9/94
दिल्ली	2	34194	24831	30/6/96
लक्षद्वीप	1	23	22	30/6/96
पांडिचेरी	1	1096	939	31/7/96

कोयला खनन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

3469. **श्रीमती वीणा वर्मा:**
श्री अजीत जोगी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला खनन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ऋण के उपयोग के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह ऋण कब तक प्राप्त हो जायेगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ङ) विश्व बैंक ने हाल ही में 43.3 मिलियन एस०डी०आर० (63 मिलियन अमरीकी डालर) के एक आई०डी०ए० ऋण की मंजूरी कोल इंडिया लिमिटेड की "कोयला क्षेत्र पर्यावरण और सामाजिक एकीकरण परियोजना" के लिए दी है। कोल इंडिया लि० को 25 विनिर्दिष्ट कोयला परियोजनाओं में पर्यावरण कार्य योजना, पुनर्वास कार्रवाई योजना, आदि को तैयार कर लिया गया है।

दिनांक 23 जुलाई, 1996 से पांच वर्षों की अवधि तक तिमाही आधार पर ऋण को प्राप्त किया जाएगा।

कोल इंडिया लि० ने "कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना" शीर्षक के अन्तर्गत एक परियोजना के लिए भी विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव किया है।

Constitutional Provision for Education of Children and Elimination of child Labour

3470. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether some demands have been made by some commissions that the Constitutional provisions of educating all children till the age of 14 and elimination of child labour be implemented;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take some action on these demands in national interest;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) While no formal communicaion from any commission regarding implementation of the Constitutional provisions of educating all the children till the age of 14 and elimination of child labour has been received, the National Human Rights Commission (NHRC) in their Annual Report for the year 1994-95 had, inter alia, recommended (i) adoption of appropriate legislation on compulsory primary education matched with necessary resources required for the purpose and (ii) expeditious and effective implementation of child labour project